अध्यक्ष महोदय : मैं भी यही कह रहा हूं।

Shri Bibudhendra Misra: We are collaborating with Russia. Two other firms have been licensed and we hope it will be sufficient.

Dr. Ranen Sen: In the statement it is admitted that there are a number of small firms which are fabricating surgical instruments for a pretty long time. Besides giving them some technical help, have the government ever considered giving any financial help to such companies, so that they can also stand on their own legs, together with the help of designs and other things which the government propose to give them and, if so, what are the steps taken by the government in this regard?

Shri Bibudhendra Misra: So far as financial aid to small-scale industries is concerned, it is administered through the State Governments under the State Aid to Industries Act. Now it has been suggested by the advisory committee on medical instruments and drugs that around a cluster of such units, there should be some set-up whereby they can be given technical assistance also.

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जो विवरण दिया गया है, उससे स्पष्ट है कि ऐसे औजार छोटे कारखानों में बनते हैं, और अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है, उससे स्पष्ट है कि कारखाना खोला गया है, वह भी हमारी जरूरतों की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे यहां जो औजार बनते हैं वे घटिया किस्म के बनते हैं, उनकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

Shri Bibudhendra Misra: I have already said that apart from the public sector undertakings, we are taking steps to improve the quality of products produced by small producers also.

Shri Indrajit Gupta: These modern surgical instruments require some special type of steel for manufacture. May I know what arrangements government has made to see that this plant which is functioning at Madras will not suffer for lack of supplies of special steel, which are in short supply?

Shri Bibudhendra Misra: As I said, the foreign exchange part of it will be financed by the Soviet Union.

Financial Help to Mine Owners

+

***1134. Shri Vishwa Nath Pandey:**
Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:

Will the Minister of **Mines and Metals** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 650 on the 3rd December, 1965 and state:

(a) whether Government have prepared a scheme to give financial help to the mine owners for developing their mines; and

(b) if so, the main features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Mines and Metals (Shri S. A. Mehdi): (a) and (b). The proposal for giving financial assistance to mine owners for developing coal mines is still under consideration of Government.

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : कितनी खानों के मालिकों ने वित्तीय सहायता की मांग की है ?

श्री सै० अ० मेहदी : अभी तक तो कोई उनकी मांग आई नहीं है। चौथे प्लान के जो अभी टारगेट्स हैं वे सब डिसकस किये जा रहे हैं और जो प्राइवेट सैक्टर है उसकी भी जो मांगें हैं उनको देखा जा रहा है। अब तक जो रिपोर्ट मिली है उसको एग्जेमिन किया जा रहा है और बहुत से उस में फैक्टर्ज हैं जिन को देखना है। इसलिये अभी उस पर कोई डिसिशन नहीं लिया गया है।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : इसके सम्बन्ध में कोई अंतरिम रिपोर्ट मिली है क्या आपको ?

श्री सै० अ० मेहदी : अभी तक कोई एसी रिपोर्ट हाल में नहीं मिली है जो बताई जा सके ।

Shri P. R. Chakraverti: Will the Government indicate the amount of loans which had been advanced by the World Bank and what portion of it has been utilised by these mine owners for developing the mines?

The Minister of Mines and Metals (Shri S. K. Dey): I do not have the exact figure. I think we have given it on the floor of this House earlier. If I remember aright, about Rs. 16 crores was offered by the World Bank and about Rs. 13 crores have been utilised by the collieries.

Shri Sham Lal Saraf: Mechanisation of these mines being a "must" to stand competition with other exporting countries in the world, may I know whether the Government has come to a decision with regard to introducing mechanisation in some of these mines; if so, on what basis it is going to be done and what is the programme for that?

Shri S. A. Mehdi: It is a question of producing 37 million tons of coal instead of 17 million tons. From 17 million tons to 37 million tons it is a rise of more than double the present capacity. It is still to be examined in what shape Government is going to assist this industry.

Shri Sham Lal Saraf: My question was about mechanisation.....

Shri S. A. Mehdi: Mechanisation and other ways of assistance are all under consideration.

Dr. Ranen Sen: Sometime back it was the decision of the Government or, rather, the recommendation of the Government to the owners of smaller mines to coalesce, to form a sort of combination or amalgamation, and Government propose to give them financial aid. May I know how far that scheme or proposal of the Government to these mine owners has fructified and what is the result of that proposal?

Shri S. K. Dey: Amalgamation is taking place at a very slow pace. I would say there is a considerable amount of resistance on the part of small mine owners to get themselves merged with each other. That is standing in the way of mechanisation and rationalisation. As the House will appreciate, we require a certain minimum base before any mechanisation can be adopted on any scale.

श्री रघुनाथ सिंह : कितने खानों के मालिकों ने अपनी खानों को माडर्नाइज करने के लिए आपके पास आवेदन पत्र भेजे हैं ?

Shri S. K. Dey: We have not received any concrete proposals from the different collieries, but we know already several big mine owners have tried to modernise their mines and others are contemplating programmes for modernisation. Our anticipation is that it will cost about Rs. 15 crores to Rs. 20 crores, during the Fourth Five Year Plan, if they are to introduce modern methods according to the target set.

श्री हुकम चन्द कछवाय : जिन खान मालिकों ने वित्तीय सहायता सरकार से मांगी है उन्हें सहायता देते समय सरकार कोई शर्त लगाने का भी क्या विचार रखती है ? यदि हां, तो कौन सी शर्त है जिस के आधार पर उन्हें यह वित्तीय सहायता दी जाएगी ?

Shri S. K. Dey: Sir, I would say, if the hon. Member will give me some indulgence, that the heart of Government is very warm but the pocket of Government is very lean; therefore, it is very difficult to give a specific answer.

श्री विभूति मिश्र : अभी कोल माइंज के बारे में उत्तर दिया गया है । कोयले

के अलावा भारत में कापर माइंज भी हैं। राखा कोपर माइंज का जो कापर है वह सब से बढ़िया कापर है। उसका एक्स-प्लोरेशन इस वास्ते नहीं हो रहा है कि सरकार के पास काफी सहूलियतें और साधन नहीं है। इसका नतीजा यह होता है कि सरकार को करोड़ों और अरबों रुपये का कापर बाहर से मंगाना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय क्या कर रहे हैं ?

Shri S. K. Dey: I thought we were discussing the difficulties of the coal mine owners in the way of modernisation. I do not wish to step into the field of copper. I should be very happy to answer the question raised by the hon. Member if he will table a separate question on the subject.

श्री विभूति मिश्र : माइंज में कोल माइंज भी आ जाती हैं, कापर माइंज भी आ जाती हैं तथा और माइंज भी आ जाती हैं।

Shri Man Singh P. Patel: Will the hon. Minister assist the establishment of co-operatives of mine-owners to solve this problem?

Mr. Speaker: It is a suggestion.

चीनी के निर्यात पर भाड़े की छूट

***1135. श्री विभूति मिश्र :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के व्यापारियों ने सरकार को एक ज्ञापन दिया है, जिस में मांग की गई है कि उत्तर भारत से जो चीनी निर्यात की जाये उसके भाड़े में पूरी छूट दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) ऐसा कोई ज्ञापन नहीं मिला है। हां, कुछ अभ्यावेदन आये जिस में यह प्रार्थना की गयी थी कि निर्यात के लिए किसी चीनी मिल से किसी भी बन्दरगाह को जो चीनी भेजी जाय उस पर एक रुपया प्रति मन की समान दर से भाड़ा लगाया जाय।

(ख) यह निर्णय हुआ है, कि यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती। फिर भी, यह सोचकर कि आयातित अनाज लादने के लिए कांडला को खाली डिब्बे भेजे जाते हैं, 1 जनवरी, 1966 से पूर्वोत्तर रेलवे के चीनी बुक करने वाली सभी स्टेशनों से निर्यात के लिए कांडला जाने वाली चीनी की भाड़ा दरें स्टेशन से स्टेशन की सामान्य दरों से 30 प्रतिशत कम कर दी गयी हैं।

श्री विभूति मिश्र : नार्दन इंडिया में काफी चीनी की मिलें हैं और वहां काफी चीनी तैयार होती हैं। साउथ में जो चीनी पैदा होती है उस चीनी को बाहर भेजा जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि वहां चीनी की कमी हो जाती है और नार्दन इंडिया से चीनी वहां भेजी जाती है। वह चीनी खर्चीली पड़ जाती है। सारे हिन्दुस्तान में चीनी की कीमतों को पूल किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार साउथ के साथ क्यों ऐसा करती है, सारे हिन्दुस्तान के साथ फेट के मामल म क्यों नहीं एक जैसा बर्ताव किया जाता है ?

डा० राम सुभग सिंह : यह एक ऐसा प्रश्न है कि जो रेल मंत्रालय से सम्बन्ध नहीं रखता है, खाद्य और कृषि मंत्रालय उस सम्बन्ध में नीति निर्धारित करता है। माननीय सदस्य ने भाड़े के बारे में जो सवाल पूछा और भाड़े से सम्बन्ध में जो निर्णय हुआ, उस को मैंने बता दिया है।